The House reassembled at two of the clock,
MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair.*

SHORT DURATION DISCUSSION ON LOSSES SUFFERED BY FARMERS DUE TO RECENT RAINS IN VARIOUS PARTS OF COUNTRY—*Contd.**

SHRI K.N. BALAGOPAL: We can lay our Special Mentions now. ...(*Interruptions*)..

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Special Mentions, now? ...(*Interruptions*)..

SHRI K.N. BALAGOPAL: We are doing like that only. In the evening we are reading. If you allow, we can lay our Special Mentions because today is the last day of the week and everybody is going. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Are you only laying? ...(*Interruptions*)... List is not distributed. ...(*Interruptions*)... I will do one thing. ...(*Interruptions*)... See, we are taking up Short Duration Discussion. It is for one hour. In the morning we have decided it. The time is one hour. At three, this discussion will be over. ...(*Interruptions*)... It is for one hour, including the reply. ...(*Interruptions*)... So, I will restrict the time accordingly. Minister may need fifteen minutes, I believe. After that we have to take two Bills. So, after this Short Discussion is over, immediately I will allow you to lay your Special Mentions, that is, at 3.00 p.m. So, you can distribute it. ...(*Interruptions*)... Now Shri Bhupinder Singh.

श्री भूपिंदर सिंह (ओडिशा) : डिप्टी चेयरमैन सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, यह जो कल से बात चल रही है, यह मुद्दा बार-बार हम हाउस में लेकर आते हैं। सर, यह देश कृषि प्रधान देश है और हमें ऐसा लगता है कि हम "कृषि प्रधान" का जो शब्द है, इसको स्लोगन बना दिया है। लेकिन दिल, दिमाग और हमारी इच्छा-शक्ति की यहां बहुत कमियां दीखती हैं जब यहां किसान की बात उठती है। सर, इस देश में अन-टाइमली रेन से जो हालत हुई है, इससे केवल किसान ही नहीं, गरीब तबका भी पीड़ित है। इस बारिश में जो ओले पड़े हैं, जब 250 से 500 ग्राम के hailstorm पड़ते हैं, मेरे यहां खबर आई है वहां 250 से 500 ग्राम के ओले पड़े हैं। इससे गरीब की जो टाइल्स हैं वह भी टूटती हैं और एस्बेस्टस के जो मकान हैं, वे भी टूटते हैं। वह टूटा घर भी किसान का ही होता है। यहां केवल उसकी खेती की ही बात नहीं है, उसके टूटे घर की भी बात है। मैं यहां सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, निवेदन कर-करके तो मैं जानता हूं कि कृषि मंत्री जी का दिल है, इसमें कोई शक नहीं है कि वे चाहते हैं। लेकिन उनके राइट में बैठे हैं हमारे फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर श्री पासवान जी, जो अभी उठकर चले गए हैं। जब बारिश हो जाती है तो एफ.सी.आई. में कहा जाता है कि Paddy में थोड़ा सा कलर लग गया है, यह वैसा क्यों नहीं है। यह गेहूं थोड़ा सा भीग गया है, यह ऐसा नहीं है। अगर उनका भी इसमें दिल आ रहा है कि ये भी कुछ मदद करना चाहेंगे तो इससे बहुत कुछ किसान को फायदा हो सकता है। उसके साथ ही जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, किसानों के इंश्योरेंस के बारे में सोचा जाए। सर, कब तक हम तसल्ली देते रहेंगे इस देश के किसान को, जिसकी पसीने की कमाई है।

---

* Further discussion continued from 3.03.2015.

अगर कहीं व्हाइट मनी इस देश में है तो वह केवल किसान के बेटे के पास है और किसान के घर की जो कमाई है वही केवल व्हाइट मनी है, बाकी और आप किसी को नहीं कह सकते कि व्हाइट मनी कौन सी है और ब्लैक मनी कौन सी है, और उन्ही के लिए आज हम सब संसद में आते हैं, उन्ही के माध्यम से यहां आकर हम बातें करते हैं। लेकिन ऐसी हममें क्या कमजोरी है कि उनका जो इंश्योरेंस है, मैं जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से कि सरकार और प्रधान मंत्री जी को भी यहां मैंने कहा था कि आपने सब के बारे में बताया, लेकिन अपने दिल में किसानों के लिए कुछ बात रखिए, इस देश में आपको मौका मिला है। आज तक ऐसा कोई नहीं है कि जो कि चीफ मिनिस्टर तीन-तीन बार रहकर ग्राउंट रिएलिटी के साथ जिसने काम किया हो और देश का प्रधान मंत्री बना हो। आज के जो हमारे प्रधान मंत्री मोदी जी हैं, उनको यह सौभाग्य मिला है जिन्होंने उनको देखा है और वे जब मुख्य मंत्री थे, वे किसानों के लिए आंदोलन करके रास्ते पर आए थे।

मैं निवेदन करता हूं कि किसान को दिए जाने वाले इंश्योरेंस के बारे में सोचा जाए। सर, आप उन्हें मुआवजा 4,500 रुपए हैक्टेयर और 9,500 रुपए हैक्टेयर देते हैं। आप देखिए, किसान अपनी फसल पर जो चीजें लगाता है, उसमें यूरिया, फर्टिलाइजर सभी के दाम बढ़े हैं। आज लेबर के डेली वेजेज बढ़ाने की बात भी चल रही है। उसके खर्चे बढ़ते गए, लेकिन उसे आज मुआवजा 4500 रुपए हैक्टेयर और इर्रिगेटेड एरिया में 9000 रुपए हैक्टेयर के हिसाब से ही मिलता है। इसके अलावा वे फल और सब्जियां वगैरह उगाते हैं, उनके लिए आप 12,000 मुआवजा देते हैं, यह बहुत कम है। इसे बढ़ाने पर विचार किया जाए। आज हमारे यूपी, बिहार के माननीय सदस्य भी चाहते हैं कि उनका मुआवजा बढ़ाया जाए। आज उनके गेहूं की फसल नीचे गिर गयी है, फिर चाहे आलू, गन्ना या मूंग दाल की या चना दाल की बात हो, हम सब चाहते हैं कि उन्हें इन सब फसलों का पैसा मिले, लेकिन वह नहीं मिलेगा। मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि आप अभी जारी मुआवजे की राशि 4,500, 9,000 और 12000 को बढ़ाइए। महोदय, मैं आप के माध्यम से मंत्री जी को होली की मुबारकवाद देता हूं और निवेदन करता हूं कि आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे आने वाले होली के पर्व पर किसानों को कुछ खुशी मिले और वह भी इस पर्व को उत्साह के साथ मना सके। आप अपनी सरकार की ताकत का इस्तेमाल कर आज ऐसा जवाब दीजिए कि किसान के मन में आशा और उम्मीद पैदा हो। धन्यवाद।

श्री उपसभापति : श्री हुसैन दलवई, सिर्फ 5 मिनट में अपनी बात कह दीजिए।

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र) : सर, मैं हालाकि महाराष्ट्र की बात करूंगा, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि पूरे देश में कुछ नहीं हुआ है। इस बेमौसमी बारिश से पूरे देश में बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन उसमें महाराष्ट्र की हालत अधिक खराब है। सर, 2011 में महाराष्ट्र में बड़ा सूखा पड़ा, जिससे किसान बहुत परेशानी में रहा। उसे जिस ढंग से मदद चाहिए थी, वह उस वक्त की सरकार ने दी। वर्ष 2012-2013 में फिर सूखा पड़ा और चार साल इसी तरह चलता रहा। वर्ष 2013-14 में भी कई जगह सूखा पड़ा, कई जगह ओले पड़े, कई जगह बाढ़ आई और उस कारण भी किसान का बहुत भारी नुकसान हुआ। वर्ष 2014-15 में कई जगह सूखा पड़ा और अभी पिछले तीन दिनों की बेमौसम की बारिश से उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।

सर, मेरे रत्नागिरी जिले में आम की फसल पूरी खत्म हो गयी है, आम की फ्लावरिंग और तैयार आम का भी बड़ा नुकसान हुआ है। सर, आम की फसल को 75 परसेंट नुकसान हुआ है। सिंदुदुर्ग में 50 परसेंट, रायगढ़ में 60 परसेंट फसल का नुकसान हुआ है। पिछले दो-तीन

[श्री हुसैन दलवई]

दिनों की बारिश से किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए सरकार को उनकी मदद करना बहुत जरूरी है। राज्य सरकार ने सूखे और अभी बीच में हुई भारी बारिश के लिए केंद्र की सरकार से साढ़े 4 हजार करोड़ रुपए की मांग की थी, लेकिन अभी तक उसे एक पैसा भी नहीं दिया गया है। यह अच्छी बात नहीं है। सर, भाजपा की सरकार वहां भी है, लेकिन मैं नहीं जानता कि किसानों की समस्याओं को केंद्र की सरकार इस तरह नजरंदाज क्यों कर रही है? सर, मराठवाड़ा के सारे जिलों में भारी नुकसान हुआ है। वहां रबी की फसल को पूरा नुकसान हुआ है। फिर कपास और गेहूं की फसल का भी नुकसान हुआ है। विदर्भ में भी यही बात है। इसके अलावा चना, अंगूर, अनार और खासकर इनके orchids सारे तबाह हो गए हैं। इस कारण मौसम्बी, संतरा, नींबू का भी नुकसान हुआ है।

इसके बारे में मेरा कहना ऐसा है कि जिस ढंग से सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए, वह मदद अभी तक नहीं हो रही है। महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन केंद्र सरकार को जिस ढंग से उनकी मदद करनी चाहिए, वह मदद अभी तक नहीं हो रही है। सोयाबीन, अनार, अंगूर, ज्वार, चना, कपास सभी फसलों का नुकसान हो गया है। यवतमाल डिस्ट्रिक्ट की पूरी फसल खत्म हो गई है। उसके बाद जालना, बीड में भी बहुत नुकसान हो गया है। मैं तो कहूंगा कि जैसे कोंकण में आम की उपज का नुकसान हो गया है, वैसे काजू में भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। उन काश्तकारों की मदद करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी कई जगह नुकसान हो गया है। कहां नुकसान नहीं हुआ?

महोदय, मैं कृषि मंत्री जी से विनती करुंगा कि यह चौथा साल है, लगातार चार साल से किसान बड़ी परेशानी में है और मैं आज आपको आंकड़े भी दूंगा कि आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या बढ़ गई है। गए साल जितनी आत्महत्याएं हुईं, इस साल ज्यादा हुई हैं। मराठवाड़ा में जहां आत्महत्या नहीं होती थी, गए साल तीन सौ लोगों ने आत्महत्या की, इस साल छह सौ, साढ़े छह सौ लोगों ने आत्महत्या की है।

श्री उपसभापतिः बस हो गया। Please conclude. ...(*Interruptions*)...

श्री हुसैन दलवईः सर, विदर्भ में गए साल सात सौ लोगों ने आत्महत्या की, इस वर्ष आठ सौ लोगों ने आत्महत्या की है। हमारा किसान जो है, आत्महत्या करने पर निर्भर हो रहा है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Thank you.

श्री हुसैन दलवईः हमारा किसान आत्महत्या क्यों करता है? उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए। इस सरकार के बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि इनकी सारी बातें होती हैं, लेकिन किसानों की ठीक से मदद नहीं होती है। किसानों की मदद करने के लिए केंद्र सरकार को चिंतन करना चाहिए। यही मेरा कहना है। धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः श्री राम नारायण डूडी। आपके पास सिर्फ चार मिनट हैं। चार मिनट में आपको अपनी बात खत्म करनी है।

श्री राम नारायण डूडी (राजस्थान)ः उपसभापति महोदय, पूरे हिंदुस्तान के अंदर दो दिन तक जो बेमौसम बरसात हुई, इस बेमौसम बरसात के कारण पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी

तैयार फसलें थीं, वे फसलें चौपट हो गईं। इसका कारण यह है कि कुछ ऐसी फसलें होती हैं, चाहे गेहूं हो, चाहे रायड़ा हो, चाहे सरसों हो, जब वह पकने में आ जाती है तो उसके बाद अगर बरसात हो तो उसका पूरा का पूरा दाना काला पड़ जाता है। जब दाना काला पड़ जाता है तो उसका मार्केट के अंदर डिवेल्युएयशन होता है, या जब उसको बेचने के लिए जाते हैं तो व्यापारी उनको आधे, औने-पौने दामों पर खरीदते हैं। इससे काश्तकार को काफी नुकसान होता है। इस बेमौसम बरसात के बाबत मेरा इतना ही निवेदन है कि पूरे प्रदेशों से आंकड़ें वगैरह इकट्ठा करने के बाद की सर्वे रिपोर्टें, गिरदारी रिपोर्टें अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन मंत्री महोदय, आप इस भरपाई वगैरह के मामले में संशोधन करें। आपका यह जो भरपाई का, मुआवजा देने का फार्मूला है, वह बहुत पुराना हो गया है। हर चीज के रेट आज बढ़ गए हैं, कल्टीवेशन के रेट बढ़ गई हैं, डीजल के भाव जैसे उस समय थे उस हिसाब से बढ़ गए हैं, बीज आज बढ़े हुए दामों पर आता है, तो काश्तकार की जो लागत है, वह बहुत ज्यादा हो गए हैं। इसको देखते हुए आपको मुआवजे के अंदर संशोधन करना पड़ेगा। यह तो पुरानी बातें हो गई हैं कि इक्यावन सौ रुपए या साढ़े चार हजार रुपए, नौ हजार रुपए दे दिए। आज हमारे यहां अनेक प्रकार से खेती हो रही है, जैसे सिंचाई की खेती, वर्षा की खेती होती है। सिंचाई की खेती में लिफ्ट इरिगेशन, ट्यूबवेल या ओपन वेल का उपयोग होता है। हम लोग, जो पश्चिमी राजस्थान से हैं या पूरे राजस्थान से आते हैं, जहां हम जीरा, ईसबगोल और धनिया वगैरह की खेती करते हैं। कृषि मंत्री महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पश्चिमी राजस्थान में ऑन एन एवरेज कम से कम 600 फीट पर पानी का लेवल है, हमारे जोधपुर साइड में मथाानिया, सोएला, वगैरह में और नागौर का कुछ बेल्ट ऐसा है, जहां 1500-1500 फीट गहरे ट्यूबवेल खोदे जाते हैं और वहां से पानी लिफ्ट करना पड़ता है, जिसे लिफ्ट करने में बहुत खर्चा भी होता है। तो ऐसे बेल्ट का अलग-अलग वर्गीकरण होना चाहिए और, जैसी स्थिति हो, उसी के आधार पर आपको मुआवजे की राशि तय करनी चाहिए।

महोदय पूरे राजस्थान के सभी किसानों को एक ही प्रकार से मुआवजा न दिया जाए। मेरा निवेदन है कि वर्गीकरण के आधार पर अलग-अलग मुआवजा दिया जाना चाहिए। राजस्थान में नहरी क्षेत्र की खेती होती है जो ग्राउंड लैवल पर होती है। एक लिफ्ट इर्रिगेशन है और एक सूखी खेती है, जिसके अंदर बरसात के पानी के बाद जमीन में जो नमी होती है, उसमें बीज बोते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे रिवाइज करें। मान लीजिए बाढ़ आ गई और बाढ़ में नदी के किनारे से एक-एक किलो मीटर बैल्ट के अंदर काश्तकारों की पूरी की पूरी जमीनें खराब हो जाती हैं। ऐसे वक्त में केवल 8100 रुपए आप उन्हें डीसिल्टिंग के लिए देते हैं। इस नॉर्म को आप को खत्म करना पड़ेगा और कुछ अन्य नॉर्म्स को रिवाइज करना पड़ेगा।

महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जिन काश्तकारों ने लोन ले रखा है, उनका ब्याज आप माफ करें। ब्याज माफ करने के साथ ही जो काश्तकार बिजली से इर्रिगेशन कर रहे हैं, उनके बिजली के बिलों को भी माफी दिलाई जाए, ताकि वे काश्तकार आगे आने वाली फसल को उगा सकें।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आज आपको एक भी काश्तकार ऐसा नहीं मिलेगा जिसने लोन नहीं लिया हो। आप चाहे रैवेन्यू रिकॉर्ड देख लें, चाहे भूमि विकास बैंक का रिकार्ड देख लें, ग्राम सेवा सोसायटी या केंद्रीय बैंकों के रिकॉर्ड देख

[श्री राम नारायण डूडी]

लें, किसी न किसी जगह से लोन लिया हुआ है और ऐसा एक भी काश्तकार नहीं है, जिसने लोन नहीं लिया हो। किसी काश्तकार का ऐसा खाता नहीं मिलेगा, जिसमें रैड एंट्री न हो। इसके कारण आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान आज भगवान पर निर्भर है। जब भगवान बरसात करता है, तो भगवान पर और यदि बरसात नहीं होती है या कोई और प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो किसान 'राज' पर निर्भर हो जाता है। यानी 'राम' या 'राज', दोनों में से किसी एक पर किसान निर्भर होता है। ऐसे समय में राज्य को अपना दायित्व निभाते हुए प्राथमिकता के आधार पर सहायता करनी चाहिए। इस बारे में मैं एक कहावत कहना चाहता हूं-

"होई साख बिगाड़ दे
कातिक फागण मैह"

महोदय, कार्तिक के महीने के अंदर हमारी खरीफ की फसल नष्ट हो जाती है। वैसे ही रबी की फसल फागुन में वर्षा होने से खत्म हो जाती है।

महोदय, आपने मुझे बोलने के समय दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, पिछले दिनों जो बेमौसम बरसात हुई, उसके कारण पूरे देश में गेहूं, तिलहन, दलहन,गन्ना और आलू आदि की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। आम की फसल को भी बहुत नुकसान हुआ है।

माननीय उपसभापति जी, इस बेमौसम बरसात में सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश के किसानों का हुआ है। किसान पूरी तरह से खेती पर निर्भर है। अगर किसान की फसल अच्छी होगी, तो उसी की वजह से उसकी जवान बेटी के हाथ पीले होने हैं, उसी से बूढ़े बाप की दवा का इंतजाम होना है, उसी से उसके बेटे की पढ़ाई का भी इंतजाम होना है। इस वर्ष मौसम का कुछ ऐसा मिजाज़ था कि फसलें अच्छी दिखाई दे रही थीं, जिसके कारण किसान बहुत प्रसन्न था, लेकिन इस बेमौसम बरसात ने किसानों को बरबाद किया है, जिसके कारण किसानों की हालत बहुत खराब हो गई है। आप स्थिति यह है कि उनके घरों में दो दिनों से खाना तक नहीं बन रहा है। लोग रोने के लिए मजबूर हैं।

श्रीमन्, किसानों की पूंजी दिन प्रति दिन कम होती जा रही है और किसान कर्ज़ में फंसता चला जा रहा है। यही कारण है, हमारे अनेक माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की कि लाखों किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं।

श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। उस क्षेत्र में एक ओर जहां सूखे के कारण बुवाई नहीं हो पाती, वहीं आधी से ज्यादा खेती पानी के अभाव में बोई नहीं जा सकती है। इसके बाद बेमौसम बरसात के कारण जो बाकी फसल थी, वह भी पूरी तरह नष्ट हो गई है। मैं आपके माध्यम से सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि कल प्रधान मंत्री जी ने भी अपने भाषण के दौरान कहा था कि इन पिछड़े क्षेत्रों की अलग से मदद करने का काम किया जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे क्षेत्र के किसानों को सुविधा प्रदान की जाए।

मान्यवर, जो किसान कर्ज़ा लेता है, जो किसान क्रेडिट कार्ड बनता है, तो उसके बनते ही जो बीमा कंपनियां होती हैं, वे उसका प्रीमियम ले लेती हैं और प्रीमियम लेने के बाद, पहले तो

कई सरकारी कंपनियां बीमा करती थीं, लेकिन अब प्राइवेट लोग भी उस क्षेत्र में आ गए हैं और बीमा कंपनियां प्रीमियम लेने के बाद कहती हैं कि पचास परसेंट से ज्यादा जहां नुकसान होगा, वहां उसकी सापेक्ष में भरपाई की जाएगी, लेकिन पचास परसेंट से कम, वह भी पूरे जिले में। श्रीमन्, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि गांव को इकाई समझा जाए। गांवों की जो खेती है, उसका आकलन किया जाए और पचास परसेंट से कम भी नुकसान हुआ है, तो बीमा कंपनियों को इस बात के लिए आदेशित किया जाए कि वे निश्चित रूप से उनकी मदद करें।

मान्यवर, मैं बुन्देलखंड क्षेत्र के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे देश में बीमा कंपनियों के द्वारा दो-तीन परसेंट प्रीमियम लिया जाता है, जबकि बुन्देलखंड क्षेत्र में पांच-छः परसेंट प्रीमियम लिया जाता है। मैं सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, कृषि पर लागत दिन-प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, इसलिए मुआवज़े की राशि भी बढ़ानी चाहिए। वसूली पूरे तरीके से स्थगित करनी चाहिए और केवल स्थगित नहीं, बल्कि उनके ब्याज की माफी करनी चाहिए, नहीं तो चक्रवृद्धि ब्याज लगाने से अगले साल किसान कर्ज़े में पूरे तरीके से फंस जाएगा।

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि बरसात को दैवी आपदा के रूप में नहीं रखा गया है। आप कहते हैं कि ओला पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, आप कहते हैं कि तूफान आ जाएगा, वह दैवी आपदा मानी जाएगी लेकिन आज इस बेमौसम बरसात के कारण पूरा देश नष्ट हो गया है और इसको दैवी आपदा नहीं माना जा रहा है। मैं इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि बेमौसम बरसात को भी दैवी आपदा के रूप में माना जाना चाहिए। ...(**समय की घंटी**)... मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि किसान को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना बहुत जरूरी है। ...(**समय की घंटी**)... हमारे देश के प्रधान मंत्री जी को सदन में इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि साठ साल होने के बाद जैसे कर्मचारी रिटायर हो जाता है, अधिकारी रिटायर हो जाता है, वैसे ही साठ साल के बाद किसान के लिए निश्चित पेंशन सुनिश्चित करनी चाहिए, जिससे किसान को ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति : चंद्रपाल जी... समाप्त कीजिए। ...(**व्यवधान**)...

डा. चंद्रपाल सिंह यादव : सामाजिक सुरक्षा मिल सके और किसान उसका लाभ उठा सके।

श्री उपसभापति : चंद्रपाल जी, समाप्त कीजिए।

डा. चंद्रपाल सिंह यादव : सर, एक मिनट... मैं इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवसाय का भी प्रबंध होना चाहिए, जैसे डेयरी है, खाद्य प्रसंस्करण है। ऐसी तमाम चीज़ों पर किसानों को प्रोत्साहित करके कि अगर by chance फसल नष्ट हो जाए, तो किसानों को राहत प्रदान करके ...(**समय की घंटी**)... श्रीमान् जी, मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने राहत तो प्रदान की है, लेकिन हम केंद्र सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं कि वह कम से कम दस हज़ार करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार को ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Nothing more will go on record. बैठिए।

डा. चंद्रपाल सिंह यादव : सहायता के लिए उपलब्ध कराने की कृपा करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Vijayalaxmi Sadhu; four minutes.

डा. विजयलक्ष्मी साधौ (मध्य प्रदेश): सर, मेरा नाम "साधु" नहीं है। मैं "साधौ" हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. You are not sadhu but 'Sadho'!

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : न "साधु", न "साध्वी", पर "साधौ" हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay; thank you. You may start now. Your time is only four minutes.

डा. विजयलक्ष्मी साधौ: सर, यहां काफी गंभीर विषय पर सभी माननीय सदस्यों ने चर्चा की है। मैं भी अपनी कुछ बात सरकार के सामने रखना चाहती हूं कि किसान इस देश का अन्नदाता है और किसान जब परेशान होता है, तो सब दुखी होते हैं। किसान से जुड़ा हुआ मज़दूर है, मज़दूर से जुड़े हुए आम लोग हैं और जिस तरह से मानवता प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसके आधार पर जो कुदरत हम लोगों से खिलवाड़ कर रही है, उसके कारण आज अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है, तो वह किसान है।

सर, पिछले दिनों जो बारिश हुई, उससे इस देश के कई प्रदेशों में गेहूं की फसल, चने की फसल, आलू की फसल, सरसों की फसल का नुकसान हुआ है। सर, मैं जिस प्रदेश से आती हूं, मध्य प्रदेश, वह भी किसानों का प्रदेश है और वहां भी बहुत बड़े किसान नहीं हैं, लेकिन छोटे-छोटे किसान, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के छोटे किसान हैं, जो अपने बच्चों को पालने के लिए तीन-तीन, चार-चार बीघा ज़मीन पर अपनी खेती करते हैं। सर, साल दर साल खेती का रकबा कम होता जा रहा है। खेती या कृषि जो पहले एक व्यापार होता था, जिससे किसान अपने बच्चों का पालन-पोषण कर, उनके स्कूल और बाकी सब काम करते थे, लेकिन आजकल खेती व्यापार का धंधा नहीं रहा। आज किसान खुद चाहता है कि उसके बच्चे और कोई धंधा अपनाएं और वे जगह-जगह शहरों की ओर पलायन करके, छोटी-छोटी दुकानें खोलकर दूसरे धंधे और व्यापार कर रहे हैं। अभी उनके साथ जो घटनाएं घटीं, इस साल फसल बहुत अच्छी थी। किसान चाहता है कि अच्छी फसल हो और जिस साल अच्छी फसल होती है, उस साल वह चाहता है कि मकान बना ले, लड़की की शादी कर ले और अपने घर को अच्छे से चलाए, लेकिन दो-तीन दिन पहले, किसान के खेत के अंदर जो फसल पककर तैयार हो गयी थी, उसके ऊपर कुदरत की मार हुई, जिससे खासकर हमारे एरिया में गेहूं की फसल पूरी गिर गयी, चने की फसल पूरी गिर गयी और आलू की फसल गलने लगी है। इसलिए अब जब गेहूं की फसल या चने की फसल आएगी, या तो उस पर दाग लग जाएगा, वह लाल हो जाएगा या बिलकुल पतला हो जाएगा, जिसके कारण किसान अपनी फसल को ठीक से बेच भी नहीं पाएगा और उसको उसका ठीक पैसा नहीं मिलेगा, लाभ नहीं मिलेगा।

माननीय उपसभापति महोदय, अगर किसान की एक वर्ष की फसल खराब होती है तो उस किसान की रीढ़ की हड्डी पांच साल के लिए झुक जाती है, वह पांच साल तक खड़ा नहीं हो पाता। इस कारण उसको इस समस्या को झेलना पड़ता है। जब वह अपने खेत को बोने के लिए तैयार करता है तो उसे समय पर बीज नहीं मिलता, बीज मिलता भी है तो अच्छी क्वालिटी का

नहीं मिलता। जैसे-तैसे करके वह उस बीज को बोता है, फसल थोड़ी बड़ी होती है तो उसको खाद नहीं मिलती और अगर खाद मिलती है तो अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जिस समय किसान को खाद की आवश्यकता थी, उस वक्त मार्किट में तो खाद अवेलेबल थी, लेकिन जो किसान सोसायटीज़ से खाद लेता है, हमारे प्रदेश के अंदर जो आदिम जाति सेवा सहकारी समितियां हैं, वहां पर कहीं भी खाद नहीं मिल रही थी, वहां से खाद नदारद थी। यूरिया की जो बोरी है, सोसायटी में वह उसको जिस कीमत पर मिलनी थी, मार्किट में जब वह उसी बोरी को ब्लैक में, डबल कीमत देकर खरीदता था, उस वक्त उसकी आत्मा क्या कहती होगी, यह हम और आप नहीं सोच सकते। पिछले साल हमारे प्रदेश में पुलिस कस्टडी में किसान को खाद का वितरण हुआ, कई जगह मार-ठुकाई भी हुई और कई जगह ट्रेन के वैगन वापस भेजने पड़े, ट्रक वापस भेजने पड़े, इस तरह के हालात मेरे प्रदेश के अंदर हुए। ...(**समय की घंटी**)... मैं यही कहना चाहती हूं कि सोसायटी में खाद नहीं है लेकिन ब्लैक मार्किट में खाद है।

श्री उपसभापति : साधौ जी, अब कन्क्लूड कीजिए।

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : सर, मैं दो मिनट का समय और लूंगी। मेरा आशय है कि...

श्री उपसभापति : दो मिनट नहीं, एक मिनट में समाप्त कीजिए। सिर्फ एक मिनट और ले लीजिए।

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : सर, बोलने तो दीजिए। वैसे ही महिलाएं कम हैं ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, I know. Only one more minute. I have already announced it.

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : सर, कल हमने प्रधान मंत्री जी का भाषण सुना। उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया – चुनावी भाषण, लेकिन दुख इस बात का हुआ कि उस भाषण के अंदर, दो दिन पहले किसान के ऊपर जो कुदरत की मार पड़ी, उसके ऊपर भी अगर वे दो शब्द बोल देते तो मैं समझती हूं कि हाउस के सभी सदस्य उनका बहुत आभार व्यक्त करते, लेकिन उन्होंने अपने भाषण में किसान का कहीं कोई जिक्र नहीं किया कि कुदरत की मार के कारण किसानों को वे क्या इंसेंटिव्स देना चाहते हैं। ...(**समय की घंटी**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All right. You have already taken five minutes. Now please conclude.

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : मैं माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहती हूं कि जो इंश्योरेंस की पॉलिसी है, उसमें किसान का सही तरह से रजिस्ट्रेशन हो।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : उसको समय पर पैसा मिले। आज जो किसान की हालत है, उसमें या तो आप उसका कर्जा माफ करें या जो वसूली कर रहे हैं– उस गरीब के ऊपर एक तो कुदरत की मार है, ऊपर से ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. That's all.

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : जो सोसायटी वाले जाते हैं और जिस तरह से उसके बैल, भैंस और उसकी कपड़े की जो ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now take your seat.

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : सर, प्लीज़ ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude.

डा. विजयलक्ष्मी साधौ : आपने मुझे समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Meghraj Jain. Please take only five minutes. Nobody will be allowed more than that. आप चार मिनट, ज्यादा से ज्यादा पांच मिनट का समय ले लीजिए।

श्री मेघराज जैन (मध्य प्रदेश) : आदरणीय उपसभापति जी, मध्य प्रदेश में वर्षा के कारण गेहूं, चने और मसूर की फसल काफी नष्ट हुई है और वर्षा के कारण जब फसल नष्ट होती है तो जैसा सबने कहा, वह बात ठीक है कि किसान वास्तव में हताश और निराश हो जाता है। केवल किसान ही नहीं, मज़दूर और उससे जुड़े हुए छोटे-छोटे व्यापारी भी उसके कारण परेशान होते हैं।

मैं अपनी बात कम समय में कहूंगा। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसकी एक प्रक्रिया है, प्रदेश सरकार आकलन करके केंद्र को रिपोर्ट भेजती है कि हमें इतना नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई की जानी चाहिए। उसके बाद केंद्र सरकार अपनी टीम भेजकर नुकसान का आकलन कराती है और फिर केंद्र सरकार पैसा भेजती है। गत दो-तीन साल में मध्य प्रदेश को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई ठीक से नहीं हो पाई है, मेरी मांग है कि इस बार ठीक से भरपाई हो। मुझे इस बात की खुशी है कि मध्य प्रदेश में किसानों को बिना ब्याज के ऋण दिया जाता है। पांच एकड़ तक जमीन रखने वाले एक किसान परिवार को तीन लाख रुपये तक का बिना ब्याज ऋण दिया जाता है। हमारे यहां ब्याज के मामले में तो किसान ठीक है। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप प्रदेश सरकार से सम्पर्क करके, वहां से आकलन रिपोर्ट मंगवाकर, अपनी टीम भेज कर किसानों को तुरंत मुआवजा दिलवाएं ताकि किसान इस मामले में ज्यादा परेशान न हों। मेरा इतना ही कहना है। धन्यवाद।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद। Now, Shri Ranjib Biswal. सिर्फ चार मिनट। My special thanks to Shri Meghraj Jain. You said what you wanted to say. जो बोलना है, वह आप बोल चुके हैं। Mr. Biswal, follow his good example.

SHRI RANJIB BISWAL (Odisha): Right, Sir. I will follow him. I thank you, Sir, for giving me this opportunity. All of us know that the agriculture sector is the biggest contributor to the Indian economy, yet each passing day sees our farmers in misery and plight. Sometimes, the farmer community thinks whether it is a blessing or a curse to be a farmer in India. Sir, every year, our country witnesses flood, super-cyclone and drought putting the farmer community in great danger. Yet when it comes to the farmer's benefit, we are far away and far behind. Each passing day sees the agricultural land of our country diminishing. Farmers are caught between the

weather god and the moneylenders. They have been harassed by the moneylenders. The Government doesn't support them in the Minimum Support Price at the ground level. The FCI doesn't buy their foodgrains. There is distress sale of foodgrains in different parts of the country. They don't get compensation for the losses they suffer due to cyclone and flood. The recent hailstorm and rain has really damaged farmers' backbone and has really put them in great misery. If I am correct, the Government agencies have said that the suicide rate of the farmers has increased this year. Since the Agricultural Minister comes from a farming background, and I also come from a farming background, I think he should be sympathetic and he should be honest on what he is going to deliver to the farmers.

The Union Budget presented this year shows that there is a decline in the allocation to the agricultural sector. I would like the Minister to justify as to why there is a decline in the allocation, why there is a cut in expenditure in the agricultural sector. Sir, for the compensation that the farmers want for damaged crop, they have to run around like anything. The total crop insurance is a big scam in our country. The farmers have to fight between the touts, the henchmen and yet selected people get the compensation. And, after running from pillar to post, when they are frustrated, they are pushed to the wall and they have nothing to do but to commit suicide.

Sir, I take the example of Odisha. Odisha has a history of flood, drought and super-cyclones. The last two super-cyclones, Phailin and Hudhud, damaged the backbone of Odisha's farmers. But at the ground level, the farmers are yet to get the compensation that was promised. Sir, I would like to the hon. Agriculture Minister to sincerely look into this because two years have passed, yet the farmers are looking for compensation and they are falling into the hands of moneylenders. ...(*Time bell rings*)... Sir, I will take only two minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, only one more minute.

SHRI RANJIB BISWAL: Sir, the recent rain and hailstorm has destroyed the standing crops, the paddy, the fruit and the vegetables in different parts of our country. Sir, till yesterday, Odisha was witnessing rains, and, there has been hailstorm. The standing crop in Odisha has also been destroyed. I would request the Minister of Agriculture to send a team to find out as to what is the extent of damage that has been caused, and, what should be the amount of compensation for that.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you.

SHRI RANJIB BISWAL: Now, since, there is no time left, I have to conclude. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I have the constraint of time.

SHRI RANJIB BISWAL: Sir, you have just given me four minutes. Sir, you spoke for one minute, and, I spoke for three minutes.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What I spoke is in your favour. Now, Shri Ananda Bhaskar Rapolu. Mr. Rapolu, my friend, please take only four minutes.

श्री आनंद भास्कर रापोलू (तेलंगाना) : माननीय उपसभापति जी, यह तो होली का समय है, यह राष्ट्रीय उत्सव है और यह रंगोली का समय है। राष्ट्रीय स्तर पर मनाई जाने वाली यह होली, हमें यह याद दिलाती है, 'रंग दे बसंती चोला'। इसके साथ ही साथ यह होली हमें 'रंग दे चुनरिया' भी याद दिलाती है। ऐसे मौके पर आई बारिश की वजह से होली की पिचकारी छूटने जैसी लग रही है।

Now, I would like to place a critical point before the Union Government. Sir, March rains are highly complicated rains. The meteorological study of 1910 and 2010 indicate that across the Asia, including India, whenever there are rains at the concluding phase of *Rabi* season and at the onset of *Kharif* season, both the farming community and the agrarian sector have faced very serious challenge. In the last 15 years, we have not come across the March rains. This time, the month of March has begun with untimely rains, and, it is warranting us to be alert about the fungal diseases. It will not end with this *Rabi* season. It will also prolong even to the *Kharif* season because of its carrying capacity of the germs and fungus.

The yellow yeast creates havoc in the fields across the nation is an important scientific point to be taken note of. Besides, Sir, after the beginning of the rains, for the initial ten hours, the north-Indian farming community took it as a grace because slight heat waves were gradually generating, and, the wheat and other crops were getting complications because of the sudden heat waves. These rains would have been supportive but after eighteen hours, the agricultural research units, in particular, the Indian Institute of Wheat and Barley Research, indicated that it was going to have very dangerous ramifications for tomorrow.

Sir, in my State, Telangana, particularly, in Nizamabad and other Districts, there have been continuous rains for the last four days. The commercial crops are stable crops there but this time, vegetables, fruits and other commercial crops are getting complications due to March rains. So, we have to look at the impending natural calamities. The climate change, the global warming and the El-Nino effect are going to harm us. These indicators have to be taken very seriously, and, we should be ready to face these type of situations.

Last year, we faced drought throughout the country, and, these untimely rains have given a challenge to the *Kharif* season. Keeping these factors in view, I urge upon the Union Government to treat this situation as a 'natural calamity'.

Not only this, Sir, during the summer season, we are going to face very serious heat conditions. Even, that is something like a natural calamity. These shall be automatically taken note of. Apart from sending teams from the Union Government for making assessment, we have to utilize the available technical tools, the scientific tools to assess the ground realities through the GIS applications in the Meteorological Department, the inputs from the revenue and other departments besides the Agriculture Ministry's information. The assessment must be made scientifically and promptly so that the delivery of compensation or the support will be helpful in the coming season. With these few suggestions, ...(*Time-bell rings*)... I would like to call upon the Union Agriculture Minister to take note of the complications of the ...(*Interruptions*)... March rains. Thank you very much.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Now, Shri Mahendra Singh Mahra; not present. Dr. Sanjay Sinh. You have got only four minutes.

डा. संजय सिंह (असम) : माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि मुझे थोड़ा समय मिला और मैं इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बना। माननीय राम गोपाल यादव जी के नोटिस पर यह चर्चा हो रही है, उनका भी आभार। मैं कल से ही सुन रहा हूँ, हमारे तमाम माननीय सदस्यों ने इस दैवी आपदा पर अपनी चिन्ताएँ व्यक्त कीं, अपने कृषक और कृषि के नुकसान की बात कही और कृषक का क्या हाल है, यह भी बयान किया। उत्तर प्रदेश में भी बहुत नुकसान हुआ है, गेहूँ, दलहन, तिलहन, आलू, तमाम फसलों का नुकसान हुआ है। मैं माननीय उपसभापति महोदय के माध्यम से आज यह विशेष बात कहना चाहता हूँ कि अक्सर हमारे देश में घटनाएँ होती हैं, दैवी आपदा होती है, कभी सूखा पड़ता है, कभी बारिश होती है, कभी और तरह-तरह के नुकसान होते हैं और हम यहां अपने माननीय सदन में नोटिस देते हैं, चर्चा होती है, सरकार की तरफ से थोड़े आश्वासन होते हैं, थोड़ा अभिभाषण होता है और यह एक रिचुअल की तरह ही रह जाता है। मैं माननीय उपसभापति जी के माध्यम से माननीय मंत्री जी से, सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत बड़े-बड़े आश्वासन देकर, बहुत बड़ी-बड़ी बातें करके वर्तमान सरकार आई है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज जो ऐसी घटनाएँ होती हैं, हमारे देश में किसानों का हाल क्या है, वह किस कंडीशन में हमारे देश को भी खिलाता है और दुनिया के बहुत सारे देशों को खिलाता है, लेकिन इसके बावजूद उसके पास बिजली नहीं होती, पानी नहीं होता, उसको खाद भी समय पर नहीं मिलती, ब्लैक से भी खरीदनी पड़ती है, तमाम दुश्वारियों के बीच से किसान हमारे यहां अन्न की पैदावार करता है। मैं आज निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं एक बार इज़राइल में था। उस समय वहां संतरे की फसल थी। विश्व की मार्केट में वहां पर बड़ा स्लम था। वहां सरकार ने फैसला किया कि किसान संतरा नहीं तोड़ेगा और सबको सूचित कर दिया कि आप लोग इसे मत तोड़िए, पिछले तीन साल के एवरेज के प्राइस से आपको पैसे दे दिए जाएँगे। वह छोटा देश है, छोटी जनसंख्या है, जमीन छोटी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर भविष्य में ऐसी कोई घटना होती है, तो क्या हम इसके लिए कोई नीतिगत फैसला करेंगे? हमारा दुर्भाग्य यह भी है कि बहुत सारे आवश्यक विषय ऐसे हैं, जो स्टेट और सेंटर के झगड़े में फँस जाते हैं। भारत सरकार की तरफ से कहा जाता है कि यह स्टेट सब्जेक्ट है, इसे प्रदेश सरकार देखे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कृषि और इस देश का किसान। हमारा

[डा. संजय सिंह]

देश कृषि प्रधान देश कहा जाता है। हमारे यहां इंश्योरेंस की भी चर्चा हुई कि कितनी गड़बड़ हो रही है। हमारे यहां तमाम और दुश्वारियों की चर्चा हुई। क्या सरकार नीतिगत फैसला लेगी कि कभी भी हमारे यहां इस तरह से दैवी आपदा होगी और किसान की खेती का नुकसान होगा, तो उसमें नीति के हिसाब से उसको फसल का दाम निश्चित तौर से मिलेगा? उसमें यह तय हो जाए कि अगर उसके ऊपर लोन है और अगर उसको माफ नहीं किया जा सकता है, तो कुछ दिनों के लिए वेवर हो सकता है। मैं उपसभापति महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूँगा कि क्या सरकार इस महत्वपूर्ण विषय पर कोई नीतिगत व्हाइट पेपर निकालेगी और भविष्य में हमारे देश के, प्रदेश के किसानों को आश्वस्त करेगी, विश्वास दिलाएगी कि भविष्य में यह निश्चित होगा कि ऐसी घटना होगी, तो इसको इतना नुकसान मान लिया जाएगा और उसका आकलन करने के बाद फसल की नुकसान का दाम दिया जाएगा? क्या उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ नीतिगत फैसला होगा? किसान का जो भी नुकसान होता है, मैं यह तो नहीं कह सकता कि आप उसके लिए बिजली, पानी और तमाम खाद इंश्योर कर दीजिए, यह तो बड़ी मुश्किल चीज़ है, मैं अपने 25-30 साल के राजनैतिक कैरियर में देख रहा हूँ। हर बार किसान गेहूँ लेकर विक्रय केंद्र जाता है, धान लेकर जाता है, गन्ना लेकर जाता है, वह 4-4, 5-5 दिन सड़कों पर गुजार देता है। वहां पर मिडिलमैन का ही फायदा होता है, अल्टीमेटली वह मिडिलमैन के बीच ही जाता है ...(**समय की घंटी**)... और अपनी फसल की होल्डिंग, उसकी कैपेसिटी न होने की वजह से ये तमाम दुश्वारियां होती हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay, Sanjayji, please conclude.

डा. संजय सिंह : मैं माननीय मंत्री जी से यही अन्तिम बात कहना चाहता हूँ कि कोई ऐसा व्हाइट पेपर निकले कि यहां पर आपत्ति काल में किसान के सामने जो भी आपदा होती है, वे उसको इसका लाभ दिला सकें।

श्री उपसभापति : श्री शरद यादव। शरद जी, मेरी प्रार्थना है कि आप चार मिनट से ज्यादा मत लीजिए।

श्री शरद यादव (बिहार): उपसभापति जी, सब लोगों ने जो बातें रखी हैं, उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। श्री राधा मोहन सिंह जी कृषि मंत्री हैं। मैं उनसे एक ही बात का निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी विकट परिस्थिति 2008 में आयी थी और मैं उस सदन में था, तो इस मामले को सबसे पहले मैंने उठाया था। उस समय की सरकार में चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने 10 हजार करोड़ रुपये उसी समय on the Floor of the House अनाउंस किया था। आज फाइनेंस मिनिस्टर यहां नहीं हैं। ...(**व्यवधान**)... नहीं, कॉमर्स मिनिस्टर इसको नहीं कर सकते। मेरी आपसे विनती है कि आप तत्काल यहां से समय तय करिए। आपकी टीम भी जाये और राज्य सरकारों के जितने भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स हैं या जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी एकदम conclave बुलाइए। इतनी विकट परिस्थिति है कि पूरा हॉर्टिकल्चर— हम लोगों के इलाके में तो आम बहुत होता है, लेकिन उसका मंजर पूरी तरह झड़ गया है। यानी इतनी तबाही या इतनी बरबादी 2008 के बाद पहली बार हो रही है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर ठहरने की जरूरत नहीं है। यह मामला इतना गम्भीर है कि आपको यह भी सूचना मिली है

कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इस बार की फसल इतनी लहलहाती हुई थी, इतनी खूबसूरत थी कि उसे मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। मेरे एक साथी अभी मुझे बता रहे थे कि उनके यहां आलू होता है। कानपुर से आगरा तक जितने भी कोल्ड स्टोरेजेज़ हैं– यानी कई तरह के नुकसान हैं। अभी इधर से हमारे एक सदस्य बोल रहे थे कि एक तरह का ही नुकसान नहीं हुआ है। जैन साहब बोल रहे थे कि बहुत तरह के नुकसान हुए हैं। इस नुकसान से किसानों को बहुत परेशानी हो रही है।

उपसभापति जी, दूसरी चीज़ कानून है। हमारे यहां इंश्योरेंस का कानून है। अब यह इंश्योरेंस का जो मामला है, तो वे जिस तरह से ब्लॉक दे देते हैं, जिस तरह से गांव दे देते हैं, जिस तरह से सर्वे करते हैं, उसमें किसी को कुछ नहीं मिलता है। यानी आप इन सारे इंश्योरेंस वालों की मीटिंग भी तत्काल बुलाइए। यदि आप इसमें देरी करेंगे, तो इतनी बड़ी तबाही को लोग झेल नहीं पाएँगे। इतनी बढ़िया फसल जो गिरी है, उसके कारण कई किसानों का तो खेत पर जाते ही हृदयाघात हो गया। तो मेरा आपसे इतनी विनती है कि इस पर तत्काल आप तुरंत एक्शन में आइए। यही एक रास्ता है। यही मेरा आपके माध्यम से उनसे निवेदन है।

श्री उपसभापतिः धन्यवाद, शरद जी। Now, Shri Bhupender Yadav will ask a question.

श्री भुपेंद्र यादव (राजस्थान): माननीय उपसभापति महोदय, मुझे इस चर्चा में एक विशेष संकट की ओर माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान दिलाना है।

सर, जहां देश में औसत वर्षा 1200 मिलीमीटर होती है, पश्चिमी राजस्थान में काफी लम्बे समय से उसकी एक-चौथाई यानी 330 मिलीमीटर वर्षा ही हो रही है। पशु धन का पालन करना हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो नार्म्स हैं, उनके हिसाब से केवल 90 दिन दिन के लिए ही सरकार के द्वारा आपदा राशि दी जाती है। वह कार्यक्रम 1 नवम्बर से शुरू हुआ था, जो 30 जनवरी को समाप्त हो गया है। यह विषय गृह मंत्रालय से भी सम्बन्धित है, परन्तु राजस्थान में पशु धन की बड़ी समस्या है, इसलिए मैं माननीय कृषि मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूँगा कि पश्चिमी राजस्थान का यह जो संकट है, इसके लिए वे कोई रास्ता निकालें। राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में जो पशु धन के पालन करने की समस्या है और विशेष रूप से जो हमारे बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों की समस्या है, उसके लिए माननीय मंत्री महोदय कोई न कोई आश्वासन जरूर दें।

SHRI NARENDRA BUDANIA (Rajasthan): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह): उपसभापति महोदय, इन्होंने एक विशेष विषय का उल्लेख कर दिया है, तो मैं बताता हूँ कि मैंने अपने मंत्रालय की ओर से, एनडीआरएफ में छूट दी जाए, इसके लिए गृह मंत्रालय को पत्र भेज दिया है। मुझे विश्वास है कि जब अगली बैठक होगी तो उसमें उसका निराकरण होगा।

महोदय, मैं इस चर्चा के लिए आभारी हूँ, क्योंकि किसानों पर इस प्रकार की आपदा आयी है। हमारे त्यागी जी ठीक ही बता रहे थे कि सरकार से जितने खफा त्यागी जी हैं, उतनी ही कुदरत किसान से खफा है। आपने यही कहा था? ...(**व्यवधान**)...

श्री के.सी. त्यागी: हम किसी से खफा नहीं हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री राधा मोहन सिंहः आप सरकार से जितने खफा हैं, उतनी ही कुदरत किसान से खफा है। तो निश्चित रूप से मुझे अभी तक जो रिपोर्ट आयी है, पहले मैं उसको रखना चाहूँगा। उसके अनुसार पिछले तीन-चार दिनों से देश के विभिन्न राज्यों में कई स्थानों पर भारी वर्षा हुई है, जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्णाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र तथा जम्मू और कश्मीर राज्यों में कई स्थानों पर, कई जगहों पर भारी वर्षा हुई है। कई जगहों पर तो 8 से 10 सेंटीमीटर तक भी वर्षा हुई है। 8-10 सेंटीमीटर का मतलब है कि वहां पर भारी वर्षा हुई है और ऐसे जो जिले हैं, जहां 8 से 10 सेंटीमीटर वर्षा हुई है, उनमें करनाल, पंजाब में अमृतसर, उत्तर प्रदेश में बरेली, कानपुर, आदि और भी हैं, जिनका नाम हम नहीं ले रहे हैं। महाराष्ट्र में यवतमाल, चंद्रपुर, अमरावती, पुणे आदि, मध्य प्रदेश में जबलपुर, खजुराहो आदि जिलों में अति-वृष्टि हुई है। कहीं-कहीं ओला वृष्टि भी हुई है। कल की रिपोर्ट में कुछ जगहों को छोड़ कर अधिकतर जगह मौसम साफ रहा है और अभी तक प्राप्त हुई रिपोर्ट के आधार पर गैर-मौसमी वर्षा के कारण कई जगहों पर फसलें प्रभावित हुई हैं और इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा विस्तृत मूल्यांकन हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी जो प्रारंभिक आकलन आया है, उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में 27 लाख हेक्टेयर, महाराष्ट्र में साढ़े सात लाख हेक्टेयर, राजस्थान में 14 लाख हेक्टेयर, पश्चिमी बंगाल में 49 हजार हेक्टेयर और पंजाब में 6 हजार हेक्टेयर फसल पर प्रभाव पड़ा है। यह प्रारंभिक आकलन है, जो राज्यों ने भेजा है और मैं लगातार तीन दिनों से या तो राज्य के मुख्य मंत्रियों से या फिर प्रधान सचिव से, कृषि मंत्री से या फिर एग्रीकल्चर के जो प्रधान सचिव हैं, उनके संपर्क में हूँ और अधिकतर राज्य सरकारों ने अपना प्रयत्न प्रारंभ किया है।

महोदय, किसानों का नुकसान हुआ है, इसमें तो किसी का दो मत नहीं हो सकता है। अब है कि उसको मिलनेवाली जो सहायता है, उस पर हम सब लोगों ने चिंता की है, जो सहायता मिलती है, वह किसान के साथ न्याय नहीं हो रहा है। इससे पूरा सदन सहमत है और खास करके जो "कृषि बीमा योजना" की बातें आईं। मैं उसके संबंध में थोड़ी चर्चा जरूर करूंगा। कल जो भाषण हुए हैं या आज भी जो भाषण हुए, उसमें निश्चित रूप से सब लोगों ने राजनीति से अलग हट कर चर्चा की। माननीय त्यागी से तिवारी जी तक थोड़ा-बहुत राजनीतिक पुट रहा होगा, नहीं तो हम सब लोगों ने और आप लोगों ने भी, त्यागी जी और तिवारी जी ने भी ...(**व्यवधान**)...

श्री के.सी. त्यागी: मंत्री जी, आप भाषणों के बजाय कुछ सुझाव दें, तो मुझे यह शब्द अच्छा लगेगा।

श्री राधा मोहन सिंहः सर, जो विचार आए हैं, वे किसानों के हित में आए हैं और मैं भी मन से, बिल्कुल प्रतिबद्धता के साथ किसान की ही बात कर रहा हूँ, इसमें राजनीति नहीं डाल रहा हूँ। माननीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि इनके पास हिम्मत नहीं है कुछ सही बात बोलने की। मैं उनको जरूर कहना चाहूंगा कि मुझमें वास्तव में यह हिम्मत नहीं है कि जब हम किसान की बात करें, तो राजनीति भी शुरू करें। यह हिम्मत हमारे पास वास्तव में नहीं है।

महोदय, यह जो "कृषि बीमा योजना" है, जब यह "राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना" शुरू हुई थी, उस समय किसानों का प्रीमियम कम था और भारत सरकार की एक एजेंसी उस काम को

करती थी। लेकिन जब दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई, तब एक modified कृषि बीमा योजना शुरू की गई। हम लोगों के सरकार में आने से पहले जब यह शुरू की गई, तो कई राज्यों ने इसका विरोध किया, तो उस समय आदरणीय कृषि मंत्री जी ने रबी की फसल तक के लिए इसको स्थगित कर दिया। फिर जब हमारी सरकार आई और खरीफ सीजन में उसको शुरू होना था, तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, आदि 8-10 राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने कहा कि हम इसको शुरू नहीं करेंगे, पहले वाली जो चल रही है, वह ज्यादा अच्छी है। इस पर मैंने इस प्रकार का आदेश दिया और उसी समय हमने घोषणा की कि आगामी वित्तीय वर्ष यानी 2015-16 में हम एक नई "कृषि आमदनी बीमा योजना" लाएंगे। अभी तक जो बीमा है, वह है "राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना", लेकिन हमने किसानों की आमदनी की बीमा योजना लाने की बात की और इसके लिए हमने सभी सम्मान्नीय मुख्य मंत्री को पत्र भी लिखा। उनके सुझाव भी आए हैं। हमने अधिकारियों के साथ चार बैठकें कीं और अभी हाल में हमने एक बैठक की, जिसमें 20 राज्यों के या तो कृषि मंत्री थे या कृषि सचिव थे और उस बैठक में चार बातें तय हुईं। उनमें से एक बात यह थी कि कुछ राज्यों ने तो मोडिफाइड कृषि बीमा योजना को शुरू किया है, लेकिन अधिकतर राज्य पुरानी योजना को ही चाहते हैं। चाहे कोई पुरानी योजना को करे, मोडिफाइड योजना को करे या "मौसम आधारित बीमा योजना" शुरू करे, यह उस राज्य की इच्छा पर है। उसी बैठक में उत्तराखंड के माननीय कृषि मंत्री जी एक प्रस्ताव लाए कि यदि कोई राज्य सरकार अपने स्तर पर कोई योजना बनाती है, तो उसको भी केंद्र माने। चूंकि इसकी क्रियान्वयन एजेंसी राज्य सरकार है, इसलिए उस बैठक में यह भी तय हो गया कि यदि कोई राज्य सरकार चाहे तो वह अपने ढंग से इसकी योजना बना सकती है, लेकिन उसकी ऐप्रूवल यहां से लेनी पड़ेगी। हमने जिस "कृषि आमदनी बीमा योजना" की घोषणा की है, वह लगभग अंतिम चरण में है और जो नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा, उस समय तक हम इस देश में निश्चित रूप से नई "कृषि आमदनी बीमा योजना" लाने वाले हैं, यह हम सदन के माध्यम से देश के किसानों को बताना चाहते हैं।

श्री शरद यादवः राधा मोहन जी, इस समय जो फसल बरबाद हुई है और वर्तमान में जो फसल बीमा है, अगर आप उसे लागू नहीं करेंगे तो अगले साल की बात अलग है। इस साल के लिए मैंने जैसा आपसे निवेदन किया कि पुराने और नये क़ानून मिलाकर जितने तरह के रास्ते निकल सकते हैं, उन पर तत्काल मीटिंग बुलाकर कोई उपाय निकालिए।

श्री राधा मोहन सिंहः अब मैं आज पर आ रहा हूँ। देश में आज जो कृषि बीमा योजना है, जिसे राज्यों ने स्वीकार किया है, उसके आधार पर हम किसानों की मदद कर सकते हैं, उसमें यह व्यवस्था है। इसके अलावा, "मौसम आधारित बीमा योजना" है, जिसे कई राज्य सरकारों ने अपनाया है। जिन-जिन राज्यों के अंदर अभी यह आपदा आई है, उनमें से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे अधिकतर राज्यों में यह "मौसम आधारित बीमा योजना" चल रही है और वहां के किसानों को इसका लाभ 45 दिनों के अंदर देना है। जो "राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना" है, उसमें उत्पादन के बाद जो उत्पादन में कमी आती है, उसकी भरपाई की जाती है, लेकिन "मौसम आधारित बीमा योजना" लगभग इन सभी राज्यों में चल रही है और इसका लाभ उन राज्यों को मिल सकता है।

श्री भूपिंदर सिंहः उसमें रिलैक्सेशन होना चाहिए, क्योंकि उन्हें कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता है। ...**(व्यवधान)**...

3.00 P.M.

श्री राधा मोहन सिंहः देखिए, बीमा की ये जितनी योजनाएँ हैं, इनमें कौन-सी एजेंसी वहाँ काम करेगी, यह राज्य सरकार को ही तय करना है। इस देश में जब से यह बीमा कम्पनी शुरू हुई है, तब से 10 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। लेकिन, मैं फिर यह कह रहा हूँ कि इसकी एजेंसी राज्य सरकारें हैं और कौन-सी बीमा एजेंसी काम करेगी, यह उन्हीं को तय करना है, इसका ठेका उन्हीं को देना है। इसके नॉर्म्स उन्हीं को तय करने हैं कि इसका एरिया ब्लॉकवाइज़ रहेगा, तहसीलवाइज़ रहेगा या पंचायतवाइज़ रहेगा। मध्य प्रदेश एक ऐसी सरकार है, जिसने इसकी नीचे की इकाई पंचायत को माना है। इसलिए उसको इसमें खर्च थोड़ा ज्यादा आ जाता है।

श्री भूपिंदर सिंहः आंध्र प्रदेश ने village, as a unit तय किया है। ...(**व्यवधान**)...

श्री राधा मोहन सिंहः राज्य सरकारें सीमाएँ तय करती हैं और कृषि बीमा योजना तथा मौसम आधारित बीमा योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूँ कि इनमें विसंगतियां हैं। इन्हीं विसंगतियों को दूर करने के लिए हम एक नई बीमा योजना लाने वाले हैं। जो भी विसंगतियां हैं, राज्य सरकार जो एजेंसी बनाती है— जैसे, वर्ष 2012 में महाराष्ट्र के अंदर जलगाँव जिले में ओले पड़े थे, उससे पहले वहां ऐसा यंत्र लगाया गया था, जो बरबादी का पता लगा सके, लेकिन जितनी बरबादी हुई, उसका आँकड़ा उसने नहीं दिया। लगभग 1000 एकड़ में केले की बरबादी हुई थी और उसने 2000 एकड़ का आँकड़ा दिया, तो निश्चित रूप से इसमें बीमा कम्पनियां गड़बड़ी करती हैं। इसलिए इसमें कौन सी बीमा एजेंसी काम करेगी, यह राज्य सरकार को ही तय करना है।

इसमें हमने यह छूट भी दी है कि आप अपने राज्य के लिए जो भी बीमा योजना बना सकते हैं, बनाएँ, लेकिन आज सवाल यह है कि आज के इस भारी संकट में जो किसान फँसे हैं, उनकी सहायता के लिए जो मौसम आधारित बीमा योजना है, उसका लाभ क्या वहां के किसानों को दिया जा सकता है? इस संबंध में लगातार ...(**व्यवधान**)...

श्री राम नाथ ठाकुरः अभी वर्षा के कारण किसानों के ऊपर जो आपदा आई है, उस पर तो आपने कोई निर्णय दिया ही नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री राधा मोहन सिंहः आपने सुना ही नहीं। मैंने वही बताया कि इससे कितना प्रभावित हुआ है, इस संबंध में एक प्रारंभिक आकलन राज्यों ने दिया है, लेकिन राज्यों को भी सर्वे करना है। वह नीचे तक जा रहा है। जो सुबह दिया वह लेटेस्ट आपको बताया। जो हमने राज्यों से बातचीत की है, जो जानकारी दी है, ऐसी व्यवस्था नहीं है कि भारत के कृषि मंत्री अपने मन से बता दें कि यहां इतना नुकसान हुआ, वहां इतना नुकसान हुआ। यह व्यवस्था नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री किरनमय नन्दा : कुछ इंटरिम रिलीफ दीजिए।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS; THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI): Let him complete. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...(*Interruptions*)...

श्री राधा मोहन सिंह : मेरी बात समाप्त हो जाने दीजिए, फिर आप पूछिए।

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: We are discussing about the untimely and uncommon rain in March. This insurance support is not going to help rabi. Only *kharif* season is dependent on your crop insurance. ...(*Interruptions*)... Treat this as a natural calamity. Then only, you can do justice. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. ...(*Interruptions*)... That's all. ...(*Interruptions*)... Mr. Rapolu, that's enough. ...(*Interruptions*)... Please. ...(*Interruptions*)... You have put forward your point. ...(*Interruptions*)... Now, hon. Minister, you can conclude. ...(*Interruptions*)...

श्री राधा मोहन सिंह : मैं बतला रहा था सहायता के विषय में। यह जो सहायता राज्यों को करना है, यह वर्षा आपदा के अंदर नहीं है लेकिन जो ओलावृष्टि हुई है, वह आपदा के अंदर है। तो जहां ओलावृष्टि हुई है, उसमें हम उससे मदद कर सकते हैं और अभी कल भी चर्चा में बताया गया कि उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है, महाराष्ट्र ने शुरू किया है और इस आपदा के पर्याप्त फंड राज्यों के पास हैं। राज्यों के पास फंड हैं तथा SDRF के पास फंड है। जब हम आज चर्चा करते हैं तो अभी किसी ने कहा कि प्रधान मंत्री जी ने किसानों की बात नहीं की। कल उन्होंने अपने भाषण में किसानों की बात भी की और आज भी मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि अभी इस वर्ष आपदा फंड में राज्यों के पास, इस बारे में हम आपको दो-चार राज्यों का उदाहरण देंगे। उत्तर प्रदेश को अभी इस वर्ष 468 करोड़ रुपया दिया था और अगले वर्ष के लिए 675 करोड़ रुपए की राशि एस.डी.आर.एफ. के अंतर्गत आवंटित की गई। अभी राजस्थान को इस वर्ष 730 करोड़ रुपए दिए गए हैं तो अगले वर्ष के लिए 1103 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसी प्रकार से पंजाब को इस वर्ष 270 करोड़ रुपए दिए गए तो अगले वर्ष के लिए 390 करोड़ रुपए दिए गए। इसी प्रकार से सभी राज्यों के लिए प्रधान मंत्री जी की प्रतिबद्धता किसानों के प्रति है और उनके ही निर्देश पर नई कृषि बीमा योजना की शुरुआत होने जा रही है। जहां तक वर्षा का आपदा में न होना है ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती विप्लव ठाकुर : आज आग लगी है और कल बुझाने जाएंगे।

श्री राधा मोहन सिंह : आज भी तो हमारी मौसम आधारित बीमा योजना चल रही है। पूरी मदद करने के लिए हम तैयार हैं। हम राज्यों के साथ सम्पर्क में हैं। राज्यों ने शुरु कर दिया है और हम पूरी सहायता करने के लिए तैयार हैं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: That's okay. ...(*Interruptions*)...

श्री राधा मोहन सिंह : जो चंद्रपाल सिंह जी ने बात रखी, बहुत अच्छी बात रखी है। वर्षा को राष्ट्रीय आपदा नहीं माना गया है। वास्तव में राज्यों के अंदर कई प्रकार की आपदाएं आती हैं जिसको SDRF या NDRF के अंदर नहीं लिया गया है। मैं गांव में रहता हूं, मुझे पता है। इसलिए एक प्रस्ताव हमने दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि होली के बाद निश्चित रूप से राज्यों को तोहफा मिलेगा कि सबको राष्ट्रीय आपदा में शामिल करें। दूसरी बात, ...(**व्यवधान**)...

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU: Kindly treat this as a natural calamity. ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: How many times you have to intervene? Sit down. ...(*Interruptions*)... This is not the way. ...(*Interruptions*)...

श्री राधा मोहन सिंह : आज हमारा देश ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Why do you respond to this? ...(*Interruptions*)... Don't respond to him ...(*Interruptions*)... How many times you have to intervene? ...(*Interruptions*)...

श्री राधा मोहन सिंह : भारत की सरकार हर प्रकार की सहायता ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There is no time. ...(*Interruptions*)... You intervene once or twice. ...(*Interruptions*)...

श्री राधा मोहन सिंह : हर प्रकार की सहायता के लिए पूरी तरह मुस्तैद है और हमारे पास पर्याप्त फंड हैं और राज्यों के पास पर्याप्त फंड हैं और अगर कहीं उनका फंड समाप्त हो जाता है तो वे हमको पत्र देंगे, फिर हमारी टीम तुरन्त जाएगी, आकलन करेगी। महोदय, मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो राज्य हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्णाटक और उत्तर प्रदेश इन राज्यों को अभी जब सूखे की आपदा आई थी तो हमने महाराष्ट्र को छोड़कर तीनों राज्यों को पैसा दिया है। जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, माननीय सांसद जी बोल रहे थे कि साढ़े चार हजार करोड़ की मांग की गई है। नहीं, चार हजार करोड़ रुपए की मांग की गई थी और 22 जिले प्रभावित थे। बाद में फिर उन्होंने स्मरण पत्र दिया कि नहीं, 26 जिले प्रभावित हुए हैं और छः हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। मैं अभी 15 दिन पहले खुद गया था। सारे एम.पीज. बैठे थे, मुख्य मंत्री बैठे थे। उनका प्रस्ताव अब एच.एल.सी. में जाने वाला है लेकिन राज्य सरकार अभी तक ढाई हजार करोड़ रुपया खर्च कर चुकी है। हम जो पैसा sanction करेंगे, उससे उनके खर्च की भरपाई होगी। महोदय, राज्यों को पूरी छूट है कि उसके पास जो फंड है, उसमें से खर्च करे और अगर वह फंड समाप्त है, तो contingency fund है, उसमें से खर्च करे। भारत सरकार पूरी भरपाई के लिए तैयार है।

महोदय, अंत में जैसा कि हमारे डा. चंद्रपाल सिंह जी ने कहा कि किसानों को पेंशन दी जाए। इस होली के अवसर पर "अटल पेंशन योजना" की जो घोषणा हुई है, वह किसानों के लिए उपहार है। देश के तमाम किसानों को इस योजना के अंतर्गत पेंशन मिल सकती है। महोदय, इस आपदा के मौके पर भारत सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ किसानों को मदद पहुंचाने के लिए तैयार है।